लार्सेन एंड टूब्रो द्वारा एक सीमेंट कारखाना स्थापित किया जाना

786. **श्री लाखो राम अग्रवाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लार्सेंस ऐंड टूब्रो का उनके द्वारा एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने के संबंध में कोई आवेदन-पत्र सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त कारखाने को स्थापित करने की स्वीकृति दिए जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय और (औद्योगिक विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) जी, नहीं ।

(ख) सीमेंट अनिवार्य लाइसेंसीकरण की सूची में नहीं आता और भारत सरकार को किसी अनुमति की जरूरत नहीं है ।

Equity of Sick Public Sector Undertakings offered to Private Parties

787. SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to offer to private parties equity upto 100 per cent of sick Public Sector Undertakings which have been referred to the BIFR; and

(b) if so, whether the jobs for workers employed in these units would be protected?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY AND DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES) (SHRI P. K. THUNGON): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग आयोग के क्षेत्रीय केंद्रों को केंद्रीय अनुदान

788. **श्री ईश दत्त यादव** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में खादी और ग्रामोद्योग के विभिन्न क्षेत्रीय केन्द्रों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का वर्ष वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार वर्ष 1992-93 के दौरान इस अनुदान राशि में वृद्धि करने का विचार रखती है ; और

(ग) उत्तर प्रदेश में खादी को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय (लघु उद्योग और कृषि तथा ग्रामीण उद्योग विभाग) में राज्य मंत्री और वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी. जे. कुरियन) : केन्द्र सरकार देश में खादी तथा ग्रामोद्योग क्षेत्र का विकास करने तथा बढ़ावा देने के लिए ऋण तथा अनुदान के रूप में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को धन मुहैया करती है । इसकी एवज में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित क्षेत्र के खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों तथा सीधे सहायता प्राप्त संस्थानों को धन मुहैया करता है । खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा विगत तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश को दी गई अनुदान राशि इस प्रकार है :—

(लाख रुपयों में)

वर्ष	अनुदान की राशि
1988-89 . .	1544.43
1989-90 . .	1627.81
1990-91 . .	1779.80

(ख) जी, नहीं ।

(ग) उत्तर प्रदेश सहित सारे देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :—

(1) उत्पाद तथा सीमा शुल्क से छूट ।